

न्यूज टुडे

सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए FCI बफर स्टॉक से अतिरिक्त चावल आवंटित किया

सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बफर स्टॉक से 2.8 मिलियन टन चावल इथेनॉल उत्पादन के लिए रियायती दरों पर देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम के अधिशेष भंडार को कम करना है।

महत्व

- ऊर्जा सुरक्षा: इथेनॉल एक नवीकरणीय और संधारणीय ईंधन है, जो आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है।
- अतिरिक्त बफर स्टॉक का इष्टतम उपयोग: FCI ने 2025-26 के लिए चावल की आर्थिक लागत (न्यूनतम समर्थन मूल्य, भंडारण, परिवहन आदि सहित) 4173 रुपये प्रति क्विंटल अनुमानित की है।
 - वर्तमान में, FCI के पास 13.58 मीट्रिक टन के बफर भंडार के मुकाबले 61 मीट्रिक टन चावल है।
- आर्थिक: यह "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह किसानों की आय दोगुनी करने और रोजगार सृजन में भी योगदान देता है।

खाद्य पदार्थों से इथेनॉल उत्पादन से संबंधित चुनौतियां

- खाद्य सुरक्षा बनाम ऊर्जा सुरक्षा: इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी प्रमुख खाद्य फसलों के अत्यधिक उपयोग के कारण खाद्य एवं पशु आहार सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
 - गन्ना और मक्का के साथ चावल संयुक्त रूप से भारत की खाद्य एवं पशु आहार प्रणालियों का मुख्य आधार है, फिर भी इन तीनों का उपयोग इथेनॉल के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जा रहा है।
- मुद्रास्फीति: इथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्य फसलों की बढ़ती मांग से उपभोक्ताओं को इनके लिए अधिक कीमतें चुकानी पड़ सकती है। साथ ही, इनकी उपलब्धता भी कम हो सकती है।

इथेनॉल के बारे में

- इथेनॉल एक प्राथमिक जैव ईंधन है, जो प्राकृतिक रूप से यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है।
- उपयोग: जैव ईंधन (मिश्रित इथेनॉल), उद्योगों में रासायनिक विलायक, एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में चिकित्सा संबंधी उपयोग।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम

- उद्देश्य: पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के विविध उद्देश्य हैं। इनमें जीवाश्म ईंधन हेतु आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत आदि शामिल हैं।
- लक्ष्य: 2025-2026 तक 20% इथेनॉल का मिश्रण करना।
- इथेनॉल मिश्रण की राह में प्रगति: यह 2014 के 1.53% से बढ़कर 2024 में 15% हो गया है।

भारत ने विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में 'कंट्री चैंपियन' की भूमिका धारण की

इस सम्मेलन के दौरान समावेशी व प्रौद्योगिकी-संचालित ग्रामीण गवर्नेंस के मॉडल के रूप में भारत की भूमि प्रबंधन संबंधी प्रमुख पहलों की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया गया। जैसे स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म।

- स्वामित्व योजना ने 68,000 वर्ग किमी का सर्वेक्षण और 1.16 ट्रिलियन रुपये मूल्य की भूमि का मुद्राकरण किया है। इस उपलब्धि के साथ यह वैश्विक स्तर पर समावेशी आर्थिक रूपांतरण के लिए एक स्केलेबल मॉडल के रूप में सामने आई है।
 - स्वामित्व योजना का उद्देश्य जून प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिये भू-खंडों का मानचित्रण करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना है।
- क्लाइमेट रिजिलिएंस, अवसंरचना के नियोजन और योजनाओं के अभिसरण को बढ़ावा देने में ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म की भूमिका को ग्लोबल साउथ के संदर्भ में काफी लाभकारी और एक उपयोगी मॉडल माना गया।
 - ग्राम मानचित्र एक भू-स्थानिक प्लानिंग प्लेटफॉर्म है, जो ग्राम पंचायतों को डेटा-संचालित व स्थानीयकृत विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाता है।

कुशल भूमि प्रबंधन प्रणाली और आर्थिक संवृद्धि

- नौकरियां और विकास: संपत्ति तक सुव्यवस्थित पहुंच से उद्यमशीलता, विस्तार करने, धन के पुनर्निवेश और वैकल्पिक आजीविका की सुविधा मिलती है।
- निजी पूंजी: पंजीकृत संपत्ति संबंधी अधिकार भू-स्वामियों को भूमि को जमानत के रूप में रखने हेतु सक्षम बनाते हैं, जिससे निजी ऋण और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।
- अवसंरचना वित्त-पोषण: आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना के लिए विश्वसनीय सरकारी राजस्व उत्पन्न होता है।
 - निम्न आय वाले देशों में भूमि और संपत्ति कर GDP में मात्र 0.6% का योगदान करते हैं, जबकि औद्योगिक देशों में यह आंकड़ा 2.2% है।
- शहरी प्रबंधन: इससे शहरों के विकास की योजना बनाने, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा करने, विकास के अवसरों की पहचान करने और आपदा जोखिमों का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है।
- खाद्य सुरक्षा: इससे भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व में सुधार द्वारा कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि हो सकती है।



मानव द्वारा एंटीबायोटिक उपयोग से वैश्विक स्तर पर नदियों में प्रदूषण के स्तर का आकलन किया गया

यह पहली बार है कि इस विषय पर कोई अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में पहली बार यह अनुमान लगाया गया है कि हर साल मनुष्यों द्वारा उपयोग की गई लगभग 8,500 टन एंटीबायोटिक दवाएं दुनिया भर की नदियों में पहुंच जाती हैं। यह कुल उपयोग का एक-तिहाई है। इसके अलावा, इनका 11% हिस्सा महासागरों या स्थलीय जलाशयों तक भी पहुंच रहा है।

एंटीबायोटिक आधारित प्रदूषण के मार्ग

- मानव शरीर में एंटीबायोटिक अपूर्ण चयापचय और अपशिष्ट जल प्रणालियों में से एंटीबायोटिक को पूर्ण रूप से न हटा पाना।
- पशुपालन और जलीय कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक उपयोग।
- दवा विनिर्माण के दौरान होने वाला रिसाव।
- जलवायु परिवर्तन बैक्टीरिया के प्रसार को बढ़ाता है। इससे क्षैतिज जीन स्थानांतरण संभव होता है और प्रतिरोध विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है।

इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वैश्विक जनसंख्या का 10% हिस्सा सतही जल के उस शीर्ष 1% के संपर्क में है, जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं की संचयी सांद्रता सबसे अधिक है।
- अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट जल नदियों में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक प्रदूषण फैलाता है।
 - घरेलू स्रोतों से आने वाली एंटीबायोटिक दवाओं का केवल 43% ही अपशिष्ट जल प्रणालियों में प्रॉसेस किया जाता है।
- दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, यदि उन सबकी लंबाई को मिलाया जाए, तो उसका एक चौथाई हिस्सा (यानी 60 लाख किलोमीटर) ऐसी जगहों पर बह रहा है, जहां उनमें एंटीबायोटिक दवाएं बहुत ज्यादा मात्रा में घुली हुई हैं। ये दवाएं इतनी ज्यादा हैं कि यह नदियों के अंदर रहने वाले जीव-जंतुओं और पादपों के लिए खतरनाक हैं।
 - इस मामले में भारत की 80% से अधिक नदियां उच्च या अति उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में आती हैं।
- एंटीबायोटिक प्रदूषण में योगदान देने वाले मुख्य एंटीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन, सेफ्ट्राइएक्सोन और सेफिक्सिम हैं।

एंटीबायोटिक प्रदूषण के बारे में

प्रभाव:

मानव स्वास्थ्य पर: एंटीबायोटिक प्रदूषण से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) बढ़ जाता है, जो 2050 तक वैश्विक स्तर पर कुल मृत्यु का प्रमुख कारण बन सकता है (WHO)।

पर्यावरण पर: इससे सूक्ष्मजीव विविधता कम हो सकती है तथा मछलियों एवं शैवाल के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण पहलें:

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR) (2017): इसका उद्देश्य विनियमन, संबंधित जागरूकता और निगरानी में सुधार करना है।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर WHO की वैश्विक कार्य योजना (2015)।

विनिर्माण प्रक्रिया से एंटीबायोटिक प्रदूषण पर WHO के दिशा-निर्देश।

प्रधान मंत्री ने नए सुरक्षा-सिद्धांत (Security Doctrine) का अनावरण किया

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने भारत के नए सुरक्षा सिद्धांत (इन्फोग्राफिक देखिए) की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह रूपरेखा आतंकवाद के प्रति भारत की 'जीरो टॉलरेंस की नीति' को दर्शाती है।

ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया गया है, जिनमें कई टॉप कमांडर और रणनीतिकार शामिल थे। ये दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।

भारत के सुरक्षा-सिद्धांत के तीन प्रमुख स्तंभ

स्तंभ	विवरण	महत्त्व
 <p>निर्णायक जवाबी-कार्रवाई</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का उत्तर सशक्त और ठोस जवाबी-कार्रवाई से दिया जाएगा। भारत अपनी शर्तों पर जवाब देगा, आतंकवाद के मूल ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया जाएगा। 	<ul style="list-style-type: none"> रणनीतिक परिवर्तन: यह सैन्य जवाबी-कार्रवाई को भारत की आतंकवाद-रोधी नीति में औपचारिक रूप से शामिल करता है। यह एक मजबूत और निर्णायक अप्रोच का संकेत है।
 <p>परमाणु हमले की धमकी के प्रति 'जीरो टॉलरेंस'</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारत परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस बहाने आश्रय लेने वाले आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमले किए जाएंगे। 	<ul style="list-style-type: none"> यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि भारत की आत्मरक्षा की नीति को परमाणु हमले की धमकियों से रोका नहीं जा सकता। यह भारत की पहले की संयम नीति से स्पष्ट अलगाव है।
 <p>आतंकवादी और उसे पनाह देने वालों में कोई भेद नहीं</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारत आतंकवादियों और उन्हें आश्रय देने वाली सरकारों को एक ही नजरिए से देखेगा। <ul style="list-style-type: none"> भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में देश में कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। 	<ul style="list-style-type: none"> इसका उद्देश्य उस राज्य प्रायोजित आतंकवाद (State-sponsored terrorism) को समाप्त करना है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के मूल्य कम करने से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

इस कार्यकारी आदेश का मुख्य लक्ष्य अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतों को उन कीमतों के बराबर लाना है जो अन्य समान देशों में दी जाती हैं। यह आदेश "मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN)" मूल्य निर्धारण नीति को लागू करता है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका उन दवाओं के लिए वही कीमत चुकाएगा जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे कम है। इसका सम्भवतः भारत के दवा क्षेत्रक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

वर्तमान में, अमेरिका अन्य उच्च आय वाले देशों की तुलना में समान दवाओं के लिए लगभग तीन गुना अधिक भुगतान करता है।

मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) के बारे में

- MFN सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का प्रमुख आधार है। यह नियम-आधारित व्यवस्था लागू करने का प्रयास करता है। इसके तहत व्यापार अधिकार देशों की आर्थिक या राजनीतिक शक्ति पर निर्भर नहीं होकर नियमों पर आधारित होते हैं।
- इसका तात्पर्य यह है कि एक देश को दी गई सर्वोत्तम पहुंच की शर्तें अपने आप प्रणाली में अन्य सभी देशों को प्राप्त हो जाती हैं।
- प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT), 1994 के अनुच्छेद 1 के तहत, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अन्य सभी सदस्य देशों को MFN का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है।
- WTO के समझौतों के तहत, MFN दर्जा प्राप्त देश अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते।

भारतीय फार्मा क्षेत्रक पर संभावित प्रभाव

- निर्यात संबंधी चिंताएं: भारत के फार्मा निर्यात में लगभग एक-तिहाई हिस्सा (लगभग 10 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष) संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ऐसे में इस आदेश का भारत की फार्मा कंपनियों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
- अनुसंधान पर प्रभाव: यदि अमेरिकी बाजार में दवाओं की कीमतें घटती हैं, तो फार्मा कंपनियों के मुनाफे में कमी आएगी। इससे नई दवाओं के अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए धन की कमी हो सकती है।
- घरेलू बाजार में कीमतों में वृद्धि: फार्मा कंपनियां अमेरिका में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत जैसे देशों में दवाओं की कीमतें बढ़ा सकती हैं।

अन्य सुर्खियां

कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR)

भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 के अनुसार, देश की कुल प्रजनन दर 2021 में 2.0 पर स्थिर बनी रही।

कुल प्रजनन दर (TFR) क्या है?

- TFR बच्चों की उस औसत संख्या को दर्शाता है, जो एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल (15-49 वर्ष) के अंत तक जन्म देती है।
- 2.1 की कुल प्रजनन दर को "प्रतिस्थापन दर (Replacement Rate)" कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यदि यह दर लंबे समय तक बनी रहती है, तो हर पीढ़ी में लोगों की संख्या का स्थान उतनी ही संख्या में लोग लेंगे, जब तक कि इनमें से कोई कहीं अन्य प्रवास नहीं कर लेता है।
- राज्यवार स्थिति:
 - बिहार में सबसे उच्च प्रजनन दर 3.0 दर्ज की गई।
 - दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे निम्न प्रजनन दर 1.4 रही।

जर्मेनियम (Germanium)

भारतीय दूतावास के अनुसार भारत ने चीन द्वारा लगाए गए जर्मेनियम निर्यात प्रतिबंधों के संदर्भ में चीन से औपचारिक वार्ता की।

जर्मेनियम के बारे में:

- स्वरूप: यह चांदी के समान सफेद रंग की अर्ध-धातु/उपधातु (Metalloid) है, जिसमें धातु व अधातु, दोनों के गुण होते हैं।
- प्रमुख खनिज स्रोत: जर्मेनाइट एवं आर्जिरोडाइट। ये खनिज दुर्लभ होते हैं और अधिकांश जर्मेनियम का उत्पादन जिनके उपोत्पाद और कोयले की राख से होता है।
- भौतिक गुण: भंगुर (Brittle), इन्फ्रारेड विकिरण के लिए पारदर्शी, उच्च अपवर्तनांक (High refractive index), आदि।
- उत्पादन स्थिति (2023): विश्व का 68% जर्मेनियम उत्पादन चीन में होता है। इस तरह चीन विश्व में जर्मेनियम का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
- भारत पूरी तरह से जर्मेनियम के आयात पर निर्भर है।
- प्रमुख उपयोग: सेमीकंडक्टर, फाइबर ऑप्टिक्स, इन्फ्रारेड ऑप्टिक्स, सोलर सेल, आदि में।

राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund - NDF)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय रक्षा निधि में योगदान दिया। यह योगदान सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता के प्रतीक के रूप में किया गया है।

राष्ट्रीय रक्षा निधि (NDF) के बारे में

- स्थापना: वर्ष 1962 में।
- उद्देश्य: रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकद और वस्तु के रूप में प्राप्त स्वैच्छिक दान को एकत्र करना तथा इन दानों के उपयोग का निर्णय लेना।
- उपयोग: सशस्त्र बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों एवं उनके निर्भर परिजनों के कल्याण हेतु।
- प्रशासन: यह निधि एक कार्यकारी समिति द्वारा संचालित होती है। प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। रक्षा, वित्त एवं गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
 - केंद्रीय वित्त मंत्री इस कोष के कोषाध्यक्ष हैं।
- कर छूट: आयकर अधिनियम की धारा 80(G) के अंतर्गत NDF में दिए गए सभी योगदान कर मुक्त होते हैं।

बास्केट स्नीकिंग और कन्फर्म शोमिंग

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किए हैं, जो बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शोमिंग जैसे डार्क पैटर्न्स का उपयोग कर रहे थे।

डार्क पैटर्न्स (Dark Patterns) क्या हैं?

- डार्क पैटर्न्स वे छलपूर्ण डिज़ाइन तकनीकें होती हैं, जो उपभोक्ताओं को बिना उनकी स्पष्ट सहमति के गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित या मजबूर करती हैं। ये उपभोक्ताओं के स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

बास्केट स्नीकिंग:

- यह वह तकनीक है, जिसमें उपयोगकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना उनके शॉपिंग कार्ट में चेकआउट के समय अवांछित वस्तुएं या दान राशि जोड़ दी जाती हैं।
- इसका उद्देश्य है अंतिम भुगतान राशि को परोक्ष या छद्म रूप से बढ़ा देना।

कन्फर्म शोमिंग:

- इसमें उपयोगकर्ताओं पर डर, शर्म, अपराधबोध या उपहास का उपयोग करके दबाव डाला जाता है, ताकि वे किसी सेवा को स्वीकार करें या खरीदारी करें।
- उदाहरण: किसी ऑफर को नकारने के लिए बटन पर लिखा हो – "नहीं धन्यवाद, मुझे पैसे बचाने की परवाह नहीं"।



कॉसमॉस 482

कॉसमॉस 482 लैंडर प्रोब ने पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया और हिंद महासागर में गिरा।

कॉसमॉस 482 के बारे में

- यह सोवियत संघ के वेनेरा कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसके तहत शुक्र ग्रह पर कई प्रोब भेजे गए थे।
- सूर्य से दूरी के आधार पर शुक्र दूसरा ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है।
- इसे 1972 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं जा सका।
- इसमें एक कैरीयर बस और एक लैंडर प्रोब शामिल था।



LICOMK++ ओशन सिमुलेटर

चीनी शोधकर्ताओं ने एक हाई-रिज़ॉल्यूशन महासागरीय सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है, जिसका नाम LICOMK++ है। यह प्रणाली महासागर की प्रक्रियाओं और जलवायु पैटर्न का मॉडल बनाने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है।

LICOMK++ के बारे में:

- इसे महासागर का "माइक्रोस्कोप" कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा-हाई रिज़ॉल्यूशन क्षमताएं हैं।
- यह वैज्ञानिकों को भँवरों (eddies) और तापीय परिवहन (heat transport) जैसी जटिल प्रक्रियाओं का अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।
- यह प्रणाली टाइफून, समुद्री हीटवेव और बाढ़ जैसी चरम मौसम-घटनाओं के पूर्वानुमान को कहीं अधिक सटीक बना सकती है।



PL-15 और बाइकर YIHA III

भारतीय सशस्त्र बलों ने PL-15 मिसाइल्स और बाइकर YIHA III कामिकेज़ ड्रोन्स सहित पाकिस्तान के कई हाई-टेक विदेशी हथियारों को रोका तथा उन्हें निष्क्रिय किया।

PL-15 के बारे में

- यह एक चीनी मूल की हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस, सैटेलाइट नेविगेशन और इन्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग होता है।

बाइकर YIHA III के बारे में

- यह तुर्की द्वारा निर्मित कामिकेज़ शैली (एक बार उपयोग होने वाले) लोइटरिंग ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स उच्च विस्फोटक वारहेड ले जाने में सक्षम हैं।



सर्न/ CERN का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर

वैज्ञानिकों ने सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) में सीसे को सोने में परिवर्तित करने की सूचना दी है। हालांकि, यह केवल कुछ क्षण के लिए ही हो पाया।

- इस दौरान वैज्ञानिकों ने सर्न के LHC में लगभग 86 बिलियन सोने के नाभिकों का निर्माण किया। यह सीसे के परमाणुओं के प्रकाश की गति के 99.99% पर आपस में टकराने से हुआ।

सर्न के LHC के बारे में

- यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलेरेटर है।
- LHC में 27 किलोमीटर लंबी रिंग है, जिसमें सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट लगे हैं। इसमें कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई एक्सेलेरेटर उपकरण भी हैं।
- इस एक्सेलेरेटर के अंदर दो उच्च ऊर्जा वाले पार्टिकल बीम्स को प्रकाश की गति के करीब याला कराई जाती है और फिर एक-दूसरे से टकराया जाता है।



सुर्खियों में रहे स्थल



मालदीव (राजधानी: माले)

भारत ने एक वर्ष की अवधि के लिए मालदीव को 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल (T-बिल्स) रोलओवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की।

भौगोलिक अवस्थिति:

- यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह एटोल्स समूह (कोरल द्वीपों से बने द्वीप समूह) से मिलकर बना है।
- यह एशिया का सबसे छोटा देश है और रणनीतिक रूप से हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों के नजदीक स्थित है।
- यह भारत के दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आठ डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- जलवायु: उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र; शुष्क, पूर्वोत्तर मानसून (नवंबर से मार्च); वर्षा, दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से अगस्त) से।
- प्रवाल भित्तियां: मालदीव में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, जो वैश्विक प्रवाल भित्ति क्षेत्र का लगभग 3.14% हिस्सा बनाती है।
- मालदीव में कोई नदी या धारा नहीं है।

